भारतीय जनता पार्टी
राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक
स्व0 वेदप्रकाश गोयल परिसर
रानीकोठी (नागपुर)
6 फरवरी 2009

अध्यक्षीय भाषण

मित्रों,

राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आप सभी का नागपुर में हार्दिक स्वागत है। बैगलुरू के बाद आज नागपुर में एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं दो दिवसीय राष्ट्रीय परिषद् के लिए हम यहां एकत्रित हुए हैं। बेंगुलुरू की बैठक के दौरान हमारे सामने छः राज्यों के विधानसभा चुनाव थे, और आज जब हम यहां बैठे हैं लोकसभा – 2009 का चुनाव हमारे सामने है। हम सभी जानते हैं कि आगामी लोकसभा अटल जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार और वर्तमान यूपीए सरकार के कार्यों को निश्चित रूप से जनता के समर्थन की कसौटी पर परखेगा।

आजादी के बाद से अब तक जितने भी लोकसभा चुनाव हुए वे राजनीतिक दलों के मध्य लड़े गए। 1999 और 2004 में भी केवल एक ही गठबंधन एनडीए था। यूपीए का गठन चुनाव के बाद हुआ। देश के इतिहास में पहली बार कांग्रेस ने गठबंधन के महत्व को माना है। कुछ वर्ष पूर्व पंचमढ़ी में अकेले दम पर सरकार बनाने का दावा करने वाली कांग्रेस अन्ततः गठबंधन राजनीति को स्वीकार कर रही है। **देश में पहली बार दो चुनाव पूर्व गठबंधनों के बीच सीधा मुकाबला होने जा रहा है। कांग्रेस नेतृत्व के यूपीए का स्वरूप कांग्रेस के सिकुड़ते धरातल के साथ निकलकर आया है। भाजपा नेतृत्व के एनडीए का वर्तमान स्वरूप भाजपा के राजनैतिक विस्तार के साथ उभरकर आया है। दलीय राजनीति में भाजपा ने एक छोटे दल में रूप में शुरूआत करके अपना कद कांग्रेस से बड़ा करने में सफलता हासिल की। गठबंधन राजनीति में भाजपा एक अग्रदूत बनकर उभरी और भाजपा एवं एनडीए के इस निरंतर बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अन्ततः कांग्रेस को भी इस गठबंधन राजनीति का अनुसरण करना पड़ा,** अतः यूपीए अतीत की कांग्रेस का ढहता हुआ किला है तो एनडीए भविष्य के भाजपा नेतृत्व का उगता हुआ सूरज है।

वैसे तो दोनों गठबंधनों में भारी अंतर है। एनडीए सकारात्मक है तो यूपीए भाजपा विरोध की नकारात्मक अवधारणा पर टिका है। दोनों गठबंधनों में एक और अंतर कि यूपीए में भ्रम की स्थिति तो नेतृत्व से ही प्रारंभ हो गयी है। भाजपानीत एनडीए ने यह तय किया है कि हमारी ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी होंगे। अब देश की जनता यह भी जानना चाहती है कि यूपीए की ओर से भावी प्रधानमंत्री कौन होगा?

लोकसभा चुनाव की दृष्टि से हमने कई महीने पूर्व से तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। अभी भी तैयारी चल रही है। हमें प्राणप्रण से जुटकर और भी तैयारियां करनी होगी। परिणाम अनुकूल हो, बहुमत मिले इसके लिए हमें कोई कोर–कसर नहीं छोड़नी है।

देश की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि लालकिले के प्राचीर से अगले 15 अगस्त को तिरंगा कौन फहराएगा? भाजपा कार्यकर्ताओं, भाजपा समर्थकों और देश की जनता के रूझान को देखते हुए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश की जनता भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में हमारे वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को ही चुनेगी। **हमने अटलजी को प्रधानमंत्री बनाने का**

सपना देखा था। जनता, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के अथक परिश्रम से वह सपना साकार हुआ। हमने पुनः एक सपना देखा है कि भारत के अगले प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी का यह सपना भी कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास एवं देश की जनता के सहयोग से अवश्य साकार होगा।

मित्रों,

पिछले दो वर्षों में देश में लगभग 17 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। इनमें से कांग्रेस मात्र 4 राज्यों और सहयोगी दलों को भी जोड़ लिया जाए तो केवल 6 राज्यों में चुनाव जीत पायी। इससे यह बात तो साफ हो गयी है कि कांग्रेस अखिल भारतीय स्तर पर खोखली हो रही है। कांग्रेस बड़ी पार्टी से चलते–चलते अब उस स्थिति में आ गई है कि अब वह गठबंधन के बिना नहीं रह सकती। गठबंधन के इस दौर में जनता तुलना तो जरूर करेगी कि उसे एनडीए चाहिए या यूपीए। इस विषय पर कल हम राष्ट्रीय परिषद में विस्तार से विचार करेंगे।

<u>विधानसभा चुनाव</u>

मित्रों,

पिछले नवंबर–दिसंबर माह में जिन छह राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए उनमें भाजपा ने 294 स्थानों पर विजय प्राप्त की और कांग्रेस महज 244 स्थानों पर। हमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। हम इन दोनों राज्यों में पुनः सत्तासीन हुए। मैं इस अवसर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं डॉ. रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर एवं श्री विष्णु साय सहित प्रदेश के संगठन, प्रांतीय नेतृत्व, कार्यकर्तागण और जनता–जनार्दन को इस सफलता के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने सच में इतिहास रचा है। हम राजस्थान में कुछ सीटों की कमी से सरकार बनाते–बनाते रह गये। वहीं दिल्ली में प्रदर्शन हमारी आशानुरूप नहीं रहे। पर मैं यहां कह सकता हूं कि भले ही हमें उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं हुई हो पर हम जनता की आशा के केंद्र बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी सदैव बाधाओं को लांघते आगे बढ़ती रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम हर चुनौतियों का सामना करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में विजय पताका फहरायेंगे। हाल ही में संपन्न जम्मू–कश्मीर विधानसभा चुनाव में हम एक से ग्यारह पर पहुंचे। मैं जम्मू–कश्मीर के प्रांतीय नेतृत्व, संगठन के सभी कार्यकर्ताओं के साथ–साथ आम जनता को भाजपा को मिली सफलता के लिए हार्दिक बधाई देता हूं।

<u>यूपीए का कार्यकाल</u>

कांग्रेसनीत यूपीए के कार्यकाल को देश ने बहुत करीब से देखा है। न दिशा, न दृष्टि। न विचार, न विवेक। पूरे देश में अराजकता और घोर निराशा का वातावरण निर्मित हुआ है। राजनीतिक स्वार्थ की भावना से ऐसे उटपटांग निर्णय लिए गए कि एक समय तो ऐसा लगा कि कहीं यूपीए भारत को नए विभाजन की ओर तो नहीं धकेल रही है। आजादी के बाद भारत ने राजनैतिक चौसर पर वोटों के लिए तुष्टिकरण का ऐसा तांडव पूर्व में कभी नहीं देखा।

क्या नहीं हुआ है? सच्चर कमिटी की रिपोर्ट, पोटा कानून वापिस लेना, बजट का सांप्रदायीकरण, आंध्रप्रदेश में सरकारी नौकरियों में मजहबी आरक्षण, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मजहबी आरक्षण, प्रधानमंत्री द्वारा देश के संसाधनों पर मुस्लिमों का पहला अधिकार बताना, विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप में मजहबी आधार पर भेदभाव। यही नहीं वोटों के लिए संविधान तक का उल्लंघन किया। आखिर यूपीए देश को किस दिशा में ले जाना चाहती है? विपक्ष के नाते हमने समय–समय पर चेताया पर यूपीए ने लगातार सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की।

आतंकवाद

आतंकवाद के मसले पर जहां देश को अटूट रखने की कोशिश होनी चाहिए थी वहीं विपक्ष से चर्चा तक नहीं की गयी। आज सारा देश बारूद के ढेर पर बैठा है। देश के किस कोने में आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई। 'आतंकवादी' देश की व्यवस्था को चुनौती देते रहे। अपना जाल फैलाते रहे। निरीह जनता के प्राणों की बलि ली जाती रही। पर यूपीए सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी।

मित्रों, आतंकवादियों ने मुंबई के ताज होटल पर हमला नहीं किया था, वह भारत के आत्म सम्मान और स्वाभिमान के ताज पर हमला था। भाजपा ने कभी आतंकवाद पर राजनीति नहीं की। एनडीए ने पोटा इसलिए लगाया था कि आतंकवादियों को पकड़ने में, उन्हें कानून के शिकंजे में लेने में आसानी हो, पर यूपीए ने आते ही तुष्टिकरण के लिए पोटा हटाकर पता नहीं क्या संदेश देने की कोशिश की। पोटा हटाने से आतंकवादियों के हौसले बुलंद हुए।

देश आतंकवाद से लड़ना चाहता है। जो देश चार–चार बार पाकिस्तान को शिकस्त दे सकता है उसके सामने आतंकवादी क्या मायने रखते हैं? पर जब यूपीए सरकार ही घुटने टेकने वाले निर्णय ले, तो फिर देश का आत्मसम्मान किसके साथ खड़ा होगा।

आतंकवाद के मुद्दे पर पिछले दिनों संसद सत्र में आतंकवाद विरोधी कानून बनाया गया। इसके प्रावधान पर्याप्त नहीं है लेकिन इसके बावजूद हमने केंद्र सरकार का समर्थन किया। आतंकवाद के खिलाफ हर छोटी–बड़ी मुहिम में भाजपा बढ़–चढ़कर भाग लेती रहेगी। हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी तरह, यूपीए सरकार ने संघीय जांच एजेंसी बनायी लेकिन हमारे देश के जवानों को, पुलिस को आधुनिकतम उपकरण व सुविधाएं देने के लिए ठोस पहल नहीं की।

आंतकवाद के विषय पर सरकार ने विगत साढे चार वर्षो में जिस प्रकार की नीतियां बनाई उसका परिणाम आज देश के सामने हैं। आज आतंकवाद की ज्वाला हर अंचल में धधक रही है। पिछले दिनों ही आतंकवाद में नया और अस्वभाविक आयाम जुड गया जब देश में मनोरंजन करने वाले कुछ हास्य कलाकारों को यह धमकियां मिली कि वह किसी अंडरवर्ल्ड डॉन या आतंकवादी का मजाक न उड़ाए। यह प्रमाणित करता है कि आतंकवादियों के हौसले किस कदर बढ गये है। विचार कीजिए कि यह परिस्थिति उत्पन्न क्यों हुई ?

केन्द्र में सत्ता संभालने के तुरन्त बाद यूपीए सरकार ने आतंकवाद पर सख्ती कम कर दी। सिर्फ पोटा को ही नहीं हटाया बल्कि ऐसी राजनैतिक नीतियां अपनाई जिनसे आतंवादियों का मनोबल बढ़ा। आज पूरे देश में सामान्य जनता से लेकर सरकारी कर्मचारियों और व्यापारियों तक, कलाकारों से लेकर बुद्धजीवियों तक और राजनेताओं से लेकर वकीलों और न्यायधीशों समाज का हर वर्ग आतंकवाद को लेकर जिस मनोभाव से युक्त है वह यूपीए सरकार की विगत साढे चार वर्षों की नीतियों के प्रति आक्रोश की अभिव्यक्ति कर रहा है।

पड़ोसी देश

भारत के पड़ोसी देशों में वैसे तो यूपीए सरकार के शासनकाल के दौरान उत्तरोत्तर भारत विरोधी वातावरण बनता गया। परन्तु **पाकिस्तान** में इस समय जो वातावरण है वो बेहद चिन्ताजनक है और यूपीए सरकार की पूरी की पूरी विदेशनीति की अदूरदर्शिता और अक्षमता को प्रामाणित कर रहा है।

पाकिस्तान के साथ यूपीए सरकार ने विदेश नीति एक नहीं चार भारी कूटनीतिक और रणनीतिक गलतियां अपने कार्यकाल में की।

- 6 जनवरी, 2004 को वाजपेयी सरकार के समय पाकिस्तान ने संयुक्त वक्तव्य में यह कहा था कि वह अपनी धरती का प्रयोग भारत के विरूद्ध आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं

होने देगा। परन्तु 2005 में यूपीए सरकार आने के बाद जो संयुक्त वक्तव्य जारी हुआ उसमें पाकिस्तान से अपने इस वचन का कोई उल्लेख तक नहीं कराया गया।

- 2006 में हवाना में गुट निरपेक्ष सम्मेलन के समय प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को आतंकवाद से पीड़ित देश घोषित करके आतंकवाद के विषय पर पाकिस्तान को बचाव का एक रास्ता दिया।

- भारत– पाकिस्तान के मध्य जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि हम आतंकवादी घटनाओं को शांति वार्ता में बाधा नहीं बनने देंगे। इस प्रकार आतंकवादी घटनाओं को लेकर कूटनीतिक वार्ता के द्वारा दबाव बनाने के अवसर समाप्त हो गये।

- सरकार ने सबसे बड़ी गलती भारत–पाकिस्तान के साथ एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी मैकेनिज्म के गठन की बात स्वीकार करके की। इसमें यह व्यवस्था है कि भारत–पाकिस्तान एक दूसरे को आतंकवाद संबंधी सूचना और प्रमाण देंगे। इसी का लाभ उठाकर पाकिस्तान ने मीडिया रिर्पोटों के आधार पर समझौता एक्सप्रेस विस्फोट प्रकरण में मालेगांव के आरोपी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को पाकिस्तान को सौंपने की बात की।

मुझे यहां दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुंबई हमले को लेकर भारत ने अब तक जो कदम उठाए हैं, उससे आगे जाकर कार्रवाई करनी होगी। **इस कड़ी में सर्वप्रथम भारत को ज्वाइंट टेरर मैकेनिज्म से अपने को अलग कर लेना चाहिए।** जिसकी घोषणा 16 सितंबर, 2006 को क्यूबा की राजधानी हवाना में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के बीच हुई थी। क्योंकि अब पाकिस्तान का रवैया सहयोग का नहीं बल्कि प्रतिघात करने का है। **आतंकवाद से लड़ने के मामले में किसी भी देश पर निर्भर रहने की बजाए केंद्र सरकार स्वयं ठोस कार्रवाई करे।**

उधर दक्षिण में **श्रीलंका** की सेना और लिट्टे के मध्य संघर्ष आज जिस निर्णायक मुकाम तक पहुंच रहा है उसके दूरगामी परिणाम भारत पर पड़ेगे। श्रीलंका सेना के दावे के मुताबिक लिटटे की 95 प्रतिशत शक्ति समाप्त की जा चुकी है। भारत लिटटे को आतंकवादी संगठन मानता रहा है, परन्तु हमारा यह भी मानना है कि श्रीलंका की तमिल समस्या का समाधान केवल सैनिक ताकत के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसीलिए अब जब लिट्टे की शक्ति निर्णायक रूप से समाप्त हो रही है तो श्रीलंका सरकार के लिए भी सैन्य संघर्ष से अलग एक नया वातावरण उपस्थित होता दिख रहा है। समय आ गया है कि श्रीलंका सरकार को एक नये सिरे से इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करना चाहिए।

इस हेतु सबसे पहले श्रीलंका सरकार को एक आम तमिल और लिटटे के मध्य स्पष्ट रूप से अंतर करना चाहिए। **लगभग डेढ़ से तीन लाख तमिल नागरिक जो इस क्षेत्र में फंसे है उनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए श्रीलंका सरकार को आवश्यक उपाय करने चाहिए।**

मेरा मानना है कि श्रीलंका सरकार को अब एक नये सिरे से राजनैतिक वार्ता प्रारम्भ करनी चाहिए और इसमें तमिलों के सभी समूहों को शामिल करना चाहिए। **समस्या के राजनैतिक समाधान के लिए एक ऐसा प्रस्ताव लाना चाहिए जोकि 1987 में भारत और श्रीलंका के मध्य शांति समझौते पर आधारित हो। नेपाल** में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत नई सरकार आने के बाद भी स्थिति बहुत सहज नहीं हो पा रही है। नेपाल की सत्ता में ऐसे तत्वों का प्रभाव भी बढ़ गया है, जिनकी स्वाभाविक राजनीति हिंसा पर आधारित है। नेपाल में विगत दिनों सत्ता से जुड़े संगठनों द्वारा हिंसा की घटनाएं काफी मात्रा में घटित हुई है। यह लोकतंत्र की मूलभावना के अनुरूप नहीं है। लोकतंत्र की स्थापना का उद्देश्य दमन और अत्याचार से मुक्त एक खुले विचारों वाली व्यवस्था स्थापित करने का होता है न कि सत्ता का प्रयोग करके हिंसात्मक वातावरण बनाने का। **नेपाल की सरकार को ऐसे सभी तत्वों को समर्थन अथवा संरक्षण देना तत्काल बन्द करना चाहिए जो नेपाल में किसी**

भी प्रकार की हिंसा में लिप्त है। यह नेपाल सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था की कसौटी होगी। और यह नेपाल की शान्ति प्रक्रिया को अंतिम निष्कर्ष तक ले जाने के लिए आवश्यक भी है।

महंगाई का आतंक

महंगाई से तो कांग्रेस का पुराना नाता है। गत पौने पांच साल में कांग्रेसनीत यूपीए सरकार के शासन में महंगाई लगातार बेलगाम रही। लोगों का जीना मुहाल हो गया। कांग्रेस कहती जरूर है कि वह ''आम आदमी'' के साथ है लेकिन हकीकत में उसने अपने शासनकाल मे ''आम आदमी'' के पेट पर लात मारी है। यूपीए सरकार के लगभग पूरे शासन में मुद्रास्फीति की दर लगातार आसमान की ओर रही। अब चुनावी वर्ष में आंकड़े उसे कुछ राहत दे रहे हैं वह भी मंदी के बाईप्रोडक्ट के रूप में। पर खाद्य पदार्थों की कीमतों में तो अभी भी आग लगी हुई है। गत पौने पांच वर्षों में महंगाई बढ़ती रही, लोग तबाह होते रहे लेकिन कांग्रेस निष्क्रिय रही। हां, अब कांग्रेस सक्रियता दिखा रही है। उसे पता चल गया है कि जनता बेहद आक्रोशित है और चुनाव का समय आसन्न है। जनहित को दरकिनार कर और चुनावी लाभ लेने की दृष्टि से हर फैसले करने वाली कांग्रेस के होश उड़ गए हैं। इसका खामियाजा भुगतने के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए।

आज मुद्रास्फीति की दर कम हो रही है। यह कमी सरकार के प्रयासों से नहीं बल्कि आर्थिक मंदी के कारण आ रही है। इसी कारण से वास्तविक रूप मे रोजमर्रा के उपयोग की वस्तु के दाम कम नही हो रहे है। खाद्यान्नों के दाम आज भी उच्च स्तर पर है। इस कारण से गरीब परिवार के ऊपर बहुत भारी बोझ पड़ता है। नेशनल सेम्पल सर्वे के आकडों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के बजट का 52 प्रतिशत केवल खाने पीने में व्यय हो जाता है जबकि शहरी क्षेत्र के गरीबों में यह प्रतिशत 26 है। मेरे कहने का आशय यह है कि गरीब और विशेषकर गग्रमीण क्षेत्रों के गरीबों पर मंदी और बेरोजगारी की मार तो पड़ रही है, पर मंहगाई में आती कमी का कोई लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है।

आर्थिक संकट

यूपीए सरकार की नीतियों से गत पौने पांच साल में देश में आर्थिक संकट लगातार गहराते रहे। ''विद्वान अर्थशास्त्रियों की ड्रीम टीम'' – प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, साढ़े चार वर्षों तक वित्त मंत्री रहे पी. चिदंबरम, योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया – ने देश को न जाने किस राह पर भटकाये रखा। उनकी विकास योजनाएं हवा में रहीं। सभी क्षेत्रों पर आर्थिक संकट के बादल मंडराते रहे। औद्योगिक विकास की गति ऋणात्मक हालत में बनी रही। शेयर बाजार ध्वस्त होते रहे। छोटे निवेशक लुटते रहे। रूपयों की कीमतों में गिरावटें आती रही। एनडीए के समय में देश की ताकत बनी विदेशी मुद्रा भंडार का यूपीए सरकार के समय में दिवाला निकल गया है। यही नहीं इस सरकार के शासन में घोटालों की भरमार रही। गेहूं आयात घोटाला, नरेगा में घोटाला, डीडीए घोटाला, वोल्कर घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, सत्यम प्रकरण, बालू प्रकरण ....के चलते देश की अर्थव्यवस्था निरंतर खोखली होती रही। यही कारण है यूपीए सरकार में देश विकास नहीं विनाश की ओर आगे बढ़ी है।

भारत इस समय आर्थिक मंदी और बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है। लाखों लोग हर महीने अपनी आजीविका खो रहे है। चाहे वह थिरूपुर (तमिलनाडू) के वस्त्र उद्योग से जुडे कारीगर हो या सूरत(गुजरात) के हीरा उद्योग से जुडे कारीगर हो, लाखों लाख कामगार भूखमरी के कगार पर है और आत्महत्या की भी अनेक घटनाएं प्रकाश में आ रही है। आखिर यह परिस्थितियां क्यों पैदा हुई?

यूपीए सरकार इन सारी परिस्थितियों के लिए अर्थव्यवस्था के वैश्विक संकट को उत्तरदायी मान रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि विपक्ष 9 जनवरी 2008 को जब बीएसई के सैसेक्स ने 21000 का आंकड़ा छुआ तो तत्काल वित्त मंत्री ने मीडिया में आकर कहा **''ये हमारी नीतियां है,**

भारत अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अब हम दहाई अंक की विकास दर में आ चुके है''। 28 फरवरी 2008 को जब यूपीए सरकार ने अपना अंतिम बजट पेश किया तो विद्वान अर्थशास्त्रियों की त्रिमूर्ति डा0 मनमोहन सिंह, श्री पी0 चिदम्बरम एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोन्टेक सिह अहलुवालिया ने इसी आशय की बात की। **एक बार फिर तत्कालीन वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम ने कहा कि ''ये हमारी इन्टरनल ग्रोथ है, हमारे फन्डामेन्टल्स मजबूत है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे''।** केवल 10 महीने बाद जैसे ही अर्थव्यवस्था पर संकट छाया, सरकार ने तत्काल अपना पल्लू झाड़ते हुए यह कह दिया कि यह संकट तो वैश्विक मंदी के कारण है। यदि यूपीए सरकार की नीतियां और फन्डामेन्टल्स मजबूत थे तो वे 10 महीनों में ही कैसे चरमरा गये।

वास्तविकता यह है कि यूपीए सरकार की नीतियां फन्डामेन्टली गलत थी। यूपीए के शासनकाल में लगातार ऐसी नीतियां अपनाई गई जिनके चलते वैश्विक मंदी के भारत पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के उपाय की बजाय हालात को और खराब करने का काम किया।

सरकार ने लगातार साढ़े चार वर्षों तक इन्फ्रास्ट्रक्चर को धीमा रखा जिससे रोजगार और विकास दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आर्थिक कुप्रबंधन से यूपीए सरकार ने लगातार मंहगाई बढाने का काम किया, फिर बढ़ती मंहगाई से घबरा कर बगैर सोचे समझे वित्तीय संस्थानों की नीतियों में ऐसे परिवर्तन किये जिससे लिक्वीडिटी का संकट पैदा हो गया। **उदाहरण के लिए सरकार ने बैंकों के सीआरआर को एनडीए सरकार के समय के 4.5 प्रतिशत स्तर से अक्तूबर 2008 में 9.5 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचा दिया। इसी समय में प्राइम लेंडिग रेट भी दुगना होकर 14 प्रतिशत तक पहुंच गया। इस कारण से औद्योगिक ऋण के लिए उपलब्ध पूंजी में 1 लाख करोड़ रूपये की कमी आ गई।** जिसके चलते हालात बद से बदत्तर हो गये। अक्तूबर के बाद सरकार ने अपनी नीति में बदलाव स्वीकार किया जब तक बहुत देर हो चुकी थी।

<u>किसानों की दुर्दशा</u>

कांग्रेसनीत यूपीए पूरी तरह से किसान–मजदूर विरोधी सरकार रही है। मुझे याद है कि इस सरकार के समय देश में किसानों द्वारा आत्महत्या का ऐसा दौर चला कि सारा देश स्तब्ध रह गया। अन्नदाताओं द्वारा स्वयं को मौत को गले लगाने की घटनों से सारा देश शर्मसार था। मैंने उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मांग की थी कि कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का मूलाधार है। यदि खेती और किसान की उपेक्षा समाप्त नहीं हुई तो देश में विकास का पहिया थम जाएगा। अतः किसानों की समस्या और कृषि मामलों पर संसद का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए और राजनीति से ऊपर उठकर सामूहिक रूप से एक ऐसी नीति तैयार करनी चाहिए जिससे कृषि और किसान की समस्याओं का समाधान भी हो सके और आगामी दस वर्षों के लिए कोई ठोस कार्यक्रम भी तैयार किया जाना चाहिए। **कांग्रेसनीत यूपीए सरकार ने हमारी इस मांग की ओर कतई ध्यान नहीं दिया।**

हम सभी जानते हैं कि किसानों के हित के अनेक निर्णय जैसे कृषि ऋण पर ब्याज दरों में कटौती, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि आय बीमा आदि अनेक निर्णय एनडीए सरकार के समय में हुए। कांग्रेसनीत यूपीए सरकार आयी और सभी उन्नत योजनाएं ठंडे बस्ते में डाल दी। **यूपीए ने एनडीए को श्रेय न मिलने देने की दलगत राजनीति के चलते किसानों की दुर्दशा करने की पराकाष्ठा कर दी।**

भारत में आर्थिक विकास की जो नीतियां यूपीए सरकार ने बनाई उसमें गांव, गरीब और किसान को हमेशा हाशिये पर रखा गया। आज किसानों की यह स्थिति है कि खेती के लिये लागत लगातार बढ़ रही है और भूमि लगातार कम हो रही है। आज देश में एक किसान के पास औसत भूमि 1.4 हे0 है। देश में 80 प्रतिशत किसानों के पास 2 हे0 से भी कम जमीन है। कल्पना की जा सकती है कि किसानों के आर्थिक स्रोत कितने कम है।

ऐसे में किसानों को सस्ते दाम पर कृषि ऋण उपलब्ध होना अत्यंत आवश्यक है। अटलजी के नेतृत्व वाली सरकार ने लम्बे समय से चले आ रहे कृषि ऋण पर ब्याज की दरों को 60 से 50 प्रतिशत कम कर दिया था। भाजपा शासित कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सरकारों ने कृषि ऋण पर ब्याज की दर 4 प्रतिशत तक कम कर दी है। परन्तु मेरा मानना है कि केवल ब्याज की दर कम करने और कर्ज माफी जैसी चुनावी घोषणाएँ करने से किसानों का वास्तविक हित होने वाला नहीं है। क्योंकि आज भी देश में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब अपना 84 प्रतिशत ऋण गैर–सरकारी स्रोत्र जैसे साहूकारों से लेते है। कर्ज माफी का सीधा लाभ इतने बड़े वर्ग को नई मिल पाता। इसलिए मेरा मानना है कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उनकी क्रय शक्ति बढानी होगी।

इतना ही नहीं भारत में उचित भण्डारण और परिवहन की सुविधाएं न होने के कारण उपज का एक बहुत भाग रख–रखाव में नष्ट हो जाता है। उपज नष्ट होने की भय से अकसर छोटे किसानों को अपने उत्पाद बहुत कम दामों में मजबूरन बेचने पडते है। एक अनुमान के अनुसार भारत में औसतन फसलों का 25 से 30 प्रतिशत हिस्सा उचित भण्डारण के अभाव में खराब हो जाता है। जिसका अनुमाति वार्षिक मूल्य लगभग 1.5 अरब डालर के समान होता है। यदि केवल भण्डारण और विक्रय की समूचित व्यवस्था हो जाये तो किसानों की आमदनी में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है। परन्तु यूपीए सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नही उठाया और गत वर्ष उत्पन्न खाद्यान्न संकट में भी भण्डारण का कुप्रबन्धन एक प्रमुख कारण रहा है।

विकास कार्य ठप

कांग्रेसनीत यूपीए सरकार के कार्यकाल में देश में हर दिन राजनैतिक अस्थिरता कायम रही। दुर्घटनावश सत्ता में आयी यूपीए सदैव देश में एक नहीं अनेक राजनैतिक दुर्घटनाएं करती रही। इन वर्षों में भारत की साख और धाक को गहरी चोट लगी है। हम सभी जानते हैं कि एनडीए सरकार में अटलजी के नेतृत्व में देश कहां से कहां पहुंचा था। विकास के द्वार चारों दिशाओं में खुले थे। परंतु यूपीए के आते ही विकास कार्यों की गति धीमी ही नहीं हुई बल्कि पूरी तरह रोक दी गई। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भज सड़क योजना ने विकास को नई दिशा दी। रोजगार के द्वार खुले। निवेशकों ने पूंजी लगाने का उत्तम स्थान भारत को बनाया। एनडीए शासन काल में अटलजी के नेतृत्व में पोखरण विस्फोट और कारगिल विजय ने देश के इतिहास की स्वर्णिम और रोमांचित करने वाली घटनाएं बनी। पोटा कानून आतंकवाद को मिटाने के लिए बनाया गया। सर्वशिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, शिक्षा का भारतीयकरण, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान बीमा योजना जैसे अनेक जनहितार्थ फैसले ही नहीं लिए गए वरन् उसको धरती पर साकार किया गया। कांग्रेसनीत यूपीए सरकार के आते ही इन विकास कार्यों पर रोक सी लग गयी। आखिर क्यों? सत्ता परिवर्तन का अर्थ यह नहीं होता कि पूर्व में जो दल सत्ता में थी, उसके सभी निर्णय बदल दें।

विचार आधारित रचनात्मक विरोध किया

हम पिछले पांच वर्षों से विपक्ष में हैं। राजनीति में विचार आधारित विरोध होना चाहिए, विकास आधारित नहीं। हमने यूपीए सरकार का विचार आधारित विरोध किया। हमने ''वोट के लिए तुष्टीकरण नीति'' का विरोध किया। आतंकवाद और नक्सलवाद पर यूपीए के लचर रवैये का विरोध किया। पोटा हटाने का विरोध किया। बढ़ती महंगाई पर विरोध जताया। हमने विकास कार्यों और जनहितैषी निर्णयों का कभी विरोध नहीं किया। दिक्कत तो यही रही कि कांग्रेसनीत यूपीए सरकार ने अधिकतर फैसले वोटों के मद्देनजर लिये। मुंबई हमले के बाद संसद में सरकार जो कठोर कानून लेकर आयी, वह साफ नहीं है, बावजूद हमने देशहित में उसका समर्थन किया। हमने संघीय जांच एजेंसी में तमाम कमियों के बाद भी यूपीए का समर्थन किया। भाजपा की मान्यता साफ है पहले देश फिर दल।

यूपीए का लोकतंत्र में विश्वास नहीं

पूर्व में बिहार, झारखंड और गोवा में संविधान की मूल भावना के साथ छल (फ्रॉड) करने वाली यूपीए सरकार ने विश्वास मत के दौरान संसद सदस्यों को खरीदने को लेकर जो कुछ किया गया, उसे सारा देश जानता है। सभी ने अपनी आंखों से देखा। लोकतंत्र को नोटतंत्र में बदलने की साजिश यूपीए सरकार की संसदीय और लोकतांत्रिक आस्थाओं की स्वतः पोल खोलता है। आखिर हम देश की आने वाली पीढ़ी के सामने कैसा आदर्श प्रस्तुत करना चाहते है। आज जब आम नागरिकों का वर्तमान राजनैतिक व्यवस्थाओं से मोह भंग हो रहा है और उनमें अनास्था पैदा हो रही है, तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन कांग्रेसनीत यूपीए और उनके घटक दल सपा द्वारा विश्वासमत हासिल करने के लिए जो कुछ किया उससे सारा देश शर्मशार हो गया। लोकतंत्र की नींव हिल गई। अतः ऐसी सरकार का – जो दुर्घटनावश बनी और नोटतंत्र के दम पर थमी – को एक क्षण भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है।

विश्वव्यापी आर्थिक संकट और भारत का भविष्य

विश्व पर छाया आर्थिक संकट इतना गहराता जा रहा है कि मानों पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का व्यवहारिक और वैचारिक आधार संकट के घेरे में आ रहा है। कई विद्वान तो यहां तक शंका व्यक्त करते है कि जैसे 1990–91 में साम्यवाद ने संकट देखा था कहीं वैसा ही संकट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भविष्य में न देखना पड़ जाये।

इन परिस्थितियों में मुझे देश के दो महान युगदृष्टता महापुरुषों का स्मरण आ जाता है। एक हमारे भाजपा के वैचारित अधिष्ठान के प्रणेता पं0 दीनदयाल उपाध्याय जिनकी पुध्यतिथि हम कुछ दिन बाद 11 फरवरी को मनायेंगे। और दूसरे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिसकी पुण्यतिथि अभी कुछ दिन पूर्व हमने मनायी।

मुझे याद आता है कि आज से ठीक 100 साल पहले 1909 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंद–स्वराज्य नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें उन्होंने यह कहा था कि विकास का भारतीय मॉडल किस प्रकार हमारे परम्परागत ज्ञान और अनुभव पर आधारित हो सकता है। गांधी जी ने पश्चिम के विकास मॉडल के आधार पर भारत को विकसित करने का विचार स्वराज्य के प्रतिकूल बताया था। उन्होंने पुस्तक में लिखा है कि '' हम अंग्रेज शासकों से मुक्ति चाहते हैं, अंग्रेजी राज से नहीं। हम बाघ से मुक्ति चाहते है पर खुद बाघ जैसा बनना चाहते हैं। हमारी सोच यह है कि भारत तभी खुशहाल हो सकता जब भारत इंग्लैड की तरह बन जाये। '' गांधी जी का मानना था कि विकास का यह मॉडल न भारत के लिए उचित है और न पूरे विश्व के लिए।

पहले साम्यवाद का पतन और अब विश्व में छाया पूंजी का संकट कहीं न कहीं हमें याद दिलाता है कि 100 साल पहले बापू ने जो कहा था वह कुछ–कुछ घटित होता दिखाई पड़ रहा है। शायद अब भारत के लिए गांधी के विचारों के अनुरूप आचरण करने का वक्त आ गया है।

हमें भारत के विकास का एक नया मॉडल सोचना होगा जो न रूस की नकल हो न अमेरिका की। जो भारत विकास भी करें और विश्व को विकास की एक नई दिशा भी दे। जिसकी परिकल्पना महात्मा गांधी और पं0 दीनदयाल उपाध्याय जैसे विचारकों ने की थी।

यद्यपि मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं फिर भी मेरा ये मानना है कि आर्थिक विकास के अत्यन्त केन्द्रीयकृत और पूंजीआधारित विकास के मॉडल में सदैव यह आशंका रहती है कि किसी प्रमुख केन्द्र (जैसे अमेरिका) की आर्थिक मंदी सीधे पूरे विश्व को तत्काल प्रभावित कर सकती है। महात्मा गांधी एवं पं0 दीनदयाल उपाध्याय का मूल भारतीय मॉडल उद्योगों को विकेन्द्रीकरण और केवल पूंजी के स्थान पर पूंजी तथा श्रम दोनों के सामंजस्य पर आधारित था। यह स्थानीय आवश्यकताओं और व्यवस्थाओं पर आधारित था। आज के मार्केटिंग नियमों के ठीक विपरीत बेहिसाब उपभोग के स्थान पर संयमित उपयोग पर आधारित था। क्योंकि अधिकाधिक संसाधनों का संचय करने का

मॉडल शायद किसी एक देश के लिए हितकारी हो सके पर संपूर्ण विश्व के लिए कल्याणकारी कदापि नहीं हो सकता।

कृषि और ग्रामीण उद्योगों को एक विशिष्ट स्थान दिये जाने पर आधारित था। महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज और दीनदयाल जी का ग्रामोदय के विचार इसके प्रमाण है। यह विचार आज के उच्च तकनीकी उद्योगों के साथ भी जोड़े जा सकते है। उदाहरण के लिए आज इलैक्ट्रानिक, आईटी और मनोरंजन उद्योग को काफी हद तक विकेन्द्रित करके भी बड़ी अर्थव्यवस्था में योगदान दिया जा सकता है। संचार के आधुनिक संसाधनों का प्रयोग करके सभी केन्द्रों में सामंजस्य भी रखा जा सकता है। गांधी के विचारों की युगानुकूल व्याख्या करके अर्थशास्त्री एक नये भारतीय आर्थिक विकास का मॉडल विश्व के सामने रख सकते है।

<u>युवा भारत –</u>

विगत दिनों विश्वभर में आई आर्थिक मंदी ने भारत की युवा शक्ति के सामने भी एक संकट पैदा कर दिया है। लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। विदेशों में भी लोग लगातार अपनी नौकरियॉ खो रहे हैं। **आई.एल.ओ. की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2009 में पूरे विश्व में 5 करोड़ लोग तक अपनी नौकरी गंवा सकते हैं।**

आज भारत में विश्व के सर्वाधिक युवा रहते हैं। देश की 70 फीसदी आबादी 35 वर्ष से कम है। आज आवश्यकता है कि इस युवा शक्ति की सजनात्मक क्षमता का भारत उपयोग करे जिससे देश में विकास का एक नया स्वरूप उभर सके।

भारत के युवा की सृजनात्मक शक्ति का वास्तविक विकास तभी हो सकता है जब हम पश्चिम के मॉडल का अंधानुकरण करने के स्थान पर विकास का एक ऐसा मॉडल रखे जो सिर्फ भौतिक (मैटिरियल) विकास पर आधारित न हो। बल्कि भौतिक (मैटिरियल) के साथ–साथ भावनात्मक (इमोशनल), सामाजिक (सोशल), नैतिक (मोरल) और आध्यात्मिक (स्प्रीच्यूअल) इन सभी आयामों पर युवाओं की उर्जा का विकास हो सकें। आजकल अमेरिका में अनेक विचारक युवाओं में जिस **कागनेटिव इन्टेलिजेन्स** को विकसित करने की बात करते है। वह प्राचीन भारत के इन्हीं मूल्यों पर आधारित है।

महात्मा गांधी ने भी सौ साल पहले 'हिन्द स्वराज' में ऐसे ही युवा भारत की कल्पना की थी। जो सनातन भारतीय मूल्यों के आध्यात्मिक आधार से जुड़े रहते हुए विश्व में भौतिक प्रगति का नया युग ला सकें। **भारत के युवाओं को अतीत की भ्रामक विचारधाराओं का अनुयायी नहीं बनना है। बल्कि भविष्य के अभिनव विकास का अग्रदूत बनना है। भारतीयता के तत्व के बिना भारत का युवा संपूर्ण विश्व को नेतृत्व देने वाला भावी भारत कैसे बना पायेगा। यह बात महात्मा गांधी सौ साल पहले ही समझ ली थी।**

आज सभ्यताओं के संघर्ष की बात की जाती है पर गांधी जी ने 'हिन्द स्वराज' में सभ्यताओं के संवाद की बात कहीं थी। भारत के युवाओं का यदि इस प्रकार का एक समग्र और सांगोपांग विकास किया जाए तो भारत ही इस संघर्ष में संवाद की भूमिका अदा कर सकता है।

महात्मा गांधी के स्वयंभू उत्तराधिकारी यानी कांग्रेस के लोग तो इस देश में ही आपसी वैमनस्य खड़ा करने में लगे है तो विश्व में उनके नेतृत्व का भारत सभ्यताओं का संघर्ष कैसे समाप्त करवा सकता है।

मेरे कहने का आशय यह था कि आज गांधीवाद के मूल्य आज सामाजिक, आर्थिक, कूटनीतिक आदि सभी स्तरों पर अधिकाधिक प्रासंगिक हो रहे है।

मित्रों,

कल से यहीं पर दो दिवसीय राष्ट्रीय परिषद् की बैठक प्रारंभ होगी। उस बैठक में देश की आर्थिक स्थिति, विदेश नीति, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा सहित अनेकानेक राजनैतिक, सामाजिक एवं संगठनात्मक विषयों को रखने का प्रयास करूंगा। अतः उन विषयों पर आज मैं अपना विचार नहीं रख रहा हूं।

<u>परिवर्तन का आह्वान</u>

भारतीय जनता पार्टी देश भर में विजय संकल्प रैलियों के माध्यम से जनजागरण कर रही है। संगठनात्मक स्तर पर ''हर बूथ पर भाजपा'' की योजना निरंतर चल रही है। इस अभिनव योजना का लाभ प्रत्यक्ष रूप से हमें पिछले कुछ माहों में संपन्न विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला। हम सभी जानते हैं कि आज चारों ओर से राष्ट्रवादी शक्तियों पर सुनियोजित हमला हो रहा है। ऐसे में हमें हरेक मोर्चे पर सजग और सबल रहना होगा। भाजपा देश में राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की आवाज है। पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए हमारे विरोधी साजिश रचने में जुटे हुए हैं। हमें इनका मुंहतोड़ जवाब देना होगा और ऐसा तभी संभव होगा जब हम हर हाल में अपनी विचारधारा पर अडिग रहेंगे। पार्टी के मूल्यों के प्रति समर्पित रहेंगे। हम अन्य दलों से अलग हैं, इसका आभास देश की जनता को निरंतर कराना होगा। हमें व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित और पार्टी हित को प्रमुखता देना होगा। हमारे वरिष्ठों ने अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किया है। हमें इस परंपरा को अक्षुण्ण रखना है। हमारा आचरण और अनुशासन मिसाल बने, इसका सदैव भान रखना है। हमारे संवेदनशील व्यवहार से जनता को सदैव यह अनुभूति हो कि हम उनके साथ दुख–सुख में खड़े हैं। राजनीति हमारे लिए एक मिशन है। समाज में परिवर्तन लाने का माध्यम है। हम सबके प्रेरणास्रोत पं. दीनदयाल उपाध्यायजी ने बार–बार कहा है कि हमने समाजसेवा का व्रत लिया है और हम व्यापक संदर्भ में समाज परिवर्तन चाहते हैं।

यह तभी संभव है जब हम एकजुट होकर सामूहिकता और समन्वय के साथ आगामी 'लोकसभा चुनाव' जो अप्रैल–मई माह में आसन्न है, में तन्मयता से लग जायें। हम अपने–अपने स्तर पर जुट जाएं। लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से ही बदलाव का मार्ग प्रशस्त होता है। अतः आगामी लोकसभा चुनाव हमारे लिए अवसर और चुनौती दोनों है। हम चाहते हैं कि मई 2009 में पुनः भाजपानीत एनडीए की सरकार बने। हमें इस अवसर को लक्ष्य में बदलने के लिए अपने–अपने लोकसभा क्षेत्रों में कमर कसकर मेहनत करनी होगी। जनता को एहसास कराना होगा कि भारत का भविष्य भाजपानीत एनडीए के हाथों में ही सुरक्षित है और देश को अनंत आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रबल क्षमता हमारे नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी में है।

मित्रों,

कांग्रेसनीत यूपीए की नीतियों से देश की जनता आक्रोशित है। देश की जनता यूपीए को उखाड़ फेंकना चाहती है। ऐसे माहौल में यदि हम तनिक भी चूक गए तो देश हमें माफ नहीं करेगा। यहां भाजपा के शीर्षस्थ नेतृत्व उपस्थित हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सभी अपने–अपने प्रांतों में जाकर अलख जागायेंगे और कमल का फूल खिलायेंगे। साथ ही भाजपानीत एनडीए सरकार बनायेंगे और माननीय लालकृष्ण आडवाणी को भारत का प्रधानमंत्री बनायेंगे।

****